

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 98]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 17, 1973/फाल्गुन 26, 1894

No. 98]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 17, 1973/PHALGUNA 26, 1894

इस भाग में भिन्नपृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

SURTAX

New Delhi, the 17th March 1973

S.O. 156(E).—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Companies (Profits) Surtax Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Profits) Surtax (Amendment) Rules, 1973.

(2) Rule 3 shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1972, and rule 2 shall come into force on the 1st day of April, 1973.

2. In the Companies (Profits) Surtax Rules, 1964 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 8, the following rule shall be inserted, namely:—

“8A. *Production of additional evidence before the Appellate Assistant Commissioner.*—(1) The appellant shall not be entitled to produce before the Appellate Assistant Commissioner any evidence, whether oral or documentary, other than the evidence produced by him during the course of proceedings before the Income-tax Officer, except in the following circumstances, namely:—

(a) where the Income-tax Officer has refused to admit evidence which ought to have been admitted; or

- (b) where the appellant was prevented by sufficient cause from producing the evidence which he was called upon to produce by the Income-tax Officer; or
 - (c) where the appellant was prevented by sufficient cause from producing before the Income-tax Officer any evidence which is relevant to any ground of appeal; or
 - (d) where the Income-tax Officer has made the order appealed against without giving sufficient opportunity to the appellant to adduce evidence relevant to any ground of appeal.
- (2) No evidence shall be admitted under sub-rule (1) unless the Appellate Assistant Commissioner records in writing the reasons for its admission.
- (3) The Appellate Assistant Commissioner shall not take into account any evidence produced under sub-rule (1) unless the Income-tax Officer has been allowed a reasonable opportunity:—
- (a) to examine the evidence or document or to cross-examine the witness produced by the appellant, or
 - (b) to produce any evidence or document or any witness in rebuttal of the additional evidence produced by the appellant.
- (4) Nothing contained in this rule shall affect the power of the Appellate Assistant Commissioner to direct the production of any document, or the examination of any witness, to enable him to dispose of the appeal, or for any other substantial cause including the enhancement of the assessment or penalty (whether on his own motion or on the request of the Income-tax Officer) under sub-section (4) of section 11.”

3. In the Appendix to the said rules, in Form No. 11, for paragraph 3, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“3. If you do not pay the amount on or before the period specified above, you shall be liable to pay simple interest at twelve per cent per annum from the date commencing after the end of the period aforesaid in accordance with section 220(2) of the Income-tax Act, 1961, as applied to surtax by section 18 of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964.”

[No. 316/F. No. 143(8)/72-TPI.]

O. P. BHARDWAJ, Secy.

Central Board of Direct Taxes.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Simple interest at the rate of nine per cent per annum was chargeable from or payable to assessees under certain provisions of the Income-tax Act, 1961. These provisions as well as certain other provisions, including section 156 of the Income-tax Act providing for the service of a notice of demand in a prescribed form on the assessee, have been made applicable to the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 by section 18 thereof. Section 25 of the Finance Act, 1972 has amended the relevant provisions of the Income-tax Act, 1961 to increase the rate of interest chargeable from payable to assessees, from nine per cent per annum to twelve per cent per annum, with effect from the 1st April, 1972. These amended provisions have, therefore, become applicable to the Companies (Profits) Surtax Act with effect from the said date by virtue of the provisions of section 18 thereof. In order to bring the form of notice of demand [Form No. 11 set out in the Appendix to the Companies (Profits) Surtax Rules, 1964] issued under section 156 of the Income-tax Act in line with the aforesaid amendment, it has become necessary to amend this Form retrospectively from the said date to provide for charging of interest at the enhanced rate of twelve per cent per annum—Please see rules 3 of the Companies (Profits) Surtax (Amendment) Rules 1973.

2. As the amendment to the rule is made so as to bring it into conformity with the changes made in the Act, the interest of no person would be prejudicially affected by reason of the retrospective effect being given to the said amendment.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

अधिसूचना

अधिकर

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1973

का० आ० 156(अ).—कंपनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, कंपनी (लाभ) अधिकर नियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम कंपनी (लाभ) अधिकर (संशोधन) नियम, 1973 है ।

(2) नियम 3, अप्रैल, 1972 के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा और नियम 2, अप्रैल, 1973 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा ।

2. कंपनी (लाभ) अधिकर नियम, 1964 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“8क. सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना.—(1) अपीलार्थी, सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष, उसके द्वारा आय-कर अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान पेश किए गए साक्ष्य से भिन्न, निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाए, कोई अन्य साक्ष्य पेश करने का हकदार नहीं होगा, अर्थात् :—

(क) जब आय-कर अधिकारी ने स्वीकार करने योग्य साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया हो ; या

(ख) जब आय-कर अधिकारी द्वारा आगे जाने पर साक्ष्य को पेश करने के पर्याप्त हेतुक के कारण अपीलार्थी निवारित हो गया था ; या

(ग) जब अपीलार्थी पर्याप्त हेतुक के कारण आय-कर अधिकारी के समक्षक ऐसा साक्ष्य पेश करने से निवारित हो गया था जो अपील के किसी आधार से सुसंगत है ; या

(घ) जब आय-कर अधिकारी ने वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपील के किसी आधार से सुसंगत साक्ष्य पेश करने के लिए अपीलार्थी को पर्याप्त अवसर दिए बिना जारी किया हो ।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई साक्ष्य तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि सहायक आयुक्त (अपील) इसके स्वीकार करने के कारणों को देखकर नहीं कर लेता।

(3) उपनियम (1) के अधीन पेश किया गया कोई साक्ष्य सहायक आयुक्त (अपील) द्वारा तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आय-कर अधिकारी को निम्नलिखित के लिए व्यक्ति-युक्त अवसर अनुज्ञात न कर दिया गया हो—

(क) साक्ष्य या दस्तावेज की परीक्षा या अपीलार्थी द्वारा पेश किए गए गवाह की प्रति-परीक्षा, या

(ख) अपीलार्थी द्वारा पेश किए गए अतिरिक्त साक्ष्य के खंडन के लिए कोई साक्ष्य या दस्तावेज या कोई गवाह पेश करना।

(4) इस नियम में अंतर्बिष्ट कोई बात सहायक आयुक्त (अपील) को अपील के निपटान में उसे समर्थ बनाने के लिए, या धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन किसी अन्य सारवान हेतु के लिए, जिसमें निर्धारण या शास्ति का बढ़ाया जाना सम्मिलित है (चाहे स्वप्रेरणा से या आय-कर अधिकारी की प्रार्थना पर) किसी दस्तावेज को पेश करने या किसी गवाह की परीक्षा करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

3. उक्त नियमों से संलग्न अनुबन्ध में प्ररूप 11, पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“3. यदि आप ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रकम का संदाय नहीं करते तो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 220(2) में और कंपनी (लाभ) अधिकार अधिनियम 1964 की धारा 18 के अनुसार उपरोक्त अवधि की समाप्तिके पश्चात् प्रारम्भ होने वाली तारीख से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दरपर साधारण व्याज के संदाय के दायी होंगे।”

[सं० 316/फा० सं० 143 (8)/72-टी० पी० एल०]

ओ० पी० भारद्वाज,

सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड।

व्याख्यात्मक आपन

आय-कर अधिनियम 1961 के कतिपय उपबंधों के अन्तर्गत नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण व्याज निर्धारितियों पर प्रभाय अथवा उन्हें देय था। इन उपबंधों तथा साथ ही कतिपय अन्य उपबंधों को, जिनमें आयकर अधिनियम की धारा 156 शामिल हैं, और जिनके अन्तर्गत निर्धारित फार्म में निर्धारित को मांग नोटिस सामील करने की व्यवस्था है, कम्पनी (लाभ) अधिकार अधिनियम 1964 पर, उसकी धारा 18 द्वारा लागू किया गया है। वित्त अधिनियम 1972 की धारा 25 द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के संगत उपबंधों में संशोधन किया गया है जिससे 1 अप्रैल 1972 से, निर्धारितियों पर प्रभाय अथवा उन्हें देय व्याज की दर नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष से बढ़ा कर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की जा सके। अतः ये संशोधित उपबंध, कम्पनी (लाभ) अधिकार पर, उसकी धारा 18 के उपबंधों के कारण, उक्त तारीख से लागू हो गए हैं। आयकर अधिनियम की धारा 156 के अन्तर्गत जारी किये गये मांग-नोटिस फार्म को (कम्पनी (लाभ) अधिकार नियम 1964 के परिशिष्ट में दिया गया

फार्म सं० 11) उपर्युक्त संशोधन के अनुरूप बनाने की दृष्टि से इस फार्म को उक्त तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित करना आवश्यक हो गया है ताकि बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की बड़ी हुई दर से व्याज प्रभार्य करने की व्यवस्था की जा सके—कृपया कम्पनी (नाम) अधिकर (संशोधन) नियमावली 1973 देखें ।

2. इस नियम में संशोधन चूंकि अधिनियम में किये गये परिवर्तनों के अनुरूप लाने की दृष्टि से किया गया है इसलिए उक्त संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के कारण किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

